अध्याय:8

निष्कर्ष

सांसद आदर्श ग्राम योजना जो जयप्रकाश नारायण के वर्षगाँठ पर प्रधानमन्त्री द्वारा प्रारंभ किया गया। योजना महात्मा गांधी के आदर्शों पर आधारित है, उन्ही के आदर्शों के आधार पर योजना में लक्ष्यों को निर्धारित किया गया है। योजना में पंचायत को सुदृढ़ करके, महिलाओं और सभी जातियों के लोगों को समान अधिकार दिला कर गाँव को डिजिटल गाँव बनाने का सपना देखा गया है। परन्तु योजना अपने लक्ष्यों को पूरा करने में कितना सफल हो पाया है?

जयापुर गाँव को माननीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा गोद लिया गया तथा दुल्लहपुर शंकर सिंह गाँव को तत्कालीन रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा के द्वारा। दोनों ही गाँवों को केन्द्रीय मंत्रियों द्वारा गोद लिया गया था। परन्तु दोनों गाँवों को विकसित करने के प्रयासों में जमीन आसमान का फर्क है। जयापुर गाँव के साथ प्रधानमन्त्री का नाम जुड़ना ही आकर्षण का केंद्र बन गया था। मिडिया के द्वारा भी गाँव को हाथो-हाथ लिया गया और मीडिया के द्वारा गाँव को हमेशा सुर्ख़ियों में रखा गया, नतीजतन कई सारी एनजीओ और कम्पनियाँ गाँव में विनियोग करने के लिए आकर्षित हुयी।

ये एनजीओ और कम्पनियाँ केवल ग्रामीण विकास की भावना से नहीं बल्कि गाँव से प्रधानमन्त्री का नाम जुड़े होने के कारण भी उस गाँव में विनियोग कर रही है, ऐसा इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि अगर दूसरी तरफ दुल्लहपुर को देखा जाए तो दोनों गाँवों में कोई तुलना ही नहीं है।दुलाह्पुर में कोई संस्था विनियोग नहीं करना चाहती।

जयापुर में योजना आज भी पूरी तरह अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पायी है परन्तु अलग-अलग संस्थाओं के सहयोग से काफी विकास कार्य हो रहा है। परन्तु दुल्लहपुर में में ऐसा प्रतीत होता होता है की अभी योजना की शुरुआत ही नहीं की गयी। गाँव जिस स्थिति में पहले था आज भी उसी स्थिति में है बस गाँव के नाम के साथ आदर्श गाँव जुड़ गया गया है।

योजना का लक्ष्य था की एक गाँव को आदर्श गाँव बनाकर जैसे वहाँ व्यक्तिगत विकास (स्वास्थ्य, स्वछता इत्यादि के लिए जागरूकता), मानव विकास (मेडिकल कार्ड, महिलाओं के लिए विशेष सुविधा, तकनिकी का प्रयोग), सामाजिक विकास (विकास योजनाओं में ऐच्छिक सहभागिता, खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रमों को बढ़ावा), आर्थिक विकास (स्थानीय संसाधनों का उपयोग, पशुपालन, बागबानी को बढ़ावा, मृदा परिक्षण, गोबर बैंक इत्यादि), पर्यावरणीय विकास, सामाजिक सुरक्षा, सुशासन के द्वारा अन्य गाँवों के लिए 'मॉडल' की तरह पेश किया जाएगा जिसके आधार पर अन्य गाँव भी अपना विकास कर पाएंगे। लेकिन ये अन्य गाँव के लिए आदर्श न बनकर इर्ष्या का विषय बन गए है। जयापुर के आस-पास के गाँव जैसे चन्दापुर, सिंघही इत्यादि के ग्रामीणों का कहना है की एक गाँव के लिए इतनी सारी सुविधाएं और दुसरे गाँव के लिए कुछ भी नहीं।

दुल्लहपुर गाँव जिसकी स्वयं की आवश्यकताएं ही पूरी नहीं हो पा रही तो अन्य गाँव के लिए वह आदर्श कैसे बन सकता है।

इसका कारण यह भी है की जो विकास कार्य आदर्श गाँव बनाने के लिए किये गए है वो ग्रामीणों की मदद और गाँव के स्थानीय संसाधनों का प्रयोग ना करके ऊपर से थोपे गए है, ऐसा प्रतीत होता जैसे एक गाँव के ऊपर नया गाँव थोपा गया है। यह दुसरें गाँवों के लिए आदर्श तब बन पाता जब ग्रामीण स्वयं गाँव के संसाधनों का उपयोग करके अपने विकास का रास्ता खोजते। गाँव वालों को अलग से सुविधाएं देनी आवश्यक है परन्तु वो उसका कैसे उपयोग करेंगे वो उनके ऊपर छोड़ देना होगा। गाँव में पहले से भी आवश्यकत की सभी वस्तुएं है बस लोगों को जागरुक करके उसे पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है।

गाँव में जागरूकता की कमी के कारण जी सुविधाएं ग्रामीणों को प्रदान की गयी थी उसका उपयोग और सुरक्षा भी ग्रामीण नहीं कर पा रहे है। जैसे जयापुर गाँव में बायो-टॉयलेट तथा वृक्ष लगाए गए थे परन्तु वर्तमान में स्थिति यह है की पानी की कमी के वजह से वृक्ष भी सुख गए है और सार्वजनिक बायो-टॉयलेट भी खराब हो चले है। यह सीधे-सीधे गाँव में जागरूकता की कमी को दर्शाता है।

गाँव को शायद जबरदस्ती डिजिटल बनाने का प्रयास किया जा रहा है जबकि गाँव वालों की अभी मूलभूत आवश्यकताएं भी पूरी नहीं हो पा रही है। डिजिटल गाँव बनाने से पहले आवश्यक है की गाँव में शिक्षा हो, घर हो, स्वछता हो, खाने के लिए पौष्टिक आहार मिले, पिने के लिए स्वच्छ पेयजल हो। गाँव कृषि प्रधान होते है, गाँव में अन्य सुधार के अतिरिक्त आवश्यक है की ज्यादा ध्यान कृषि की गुणवत्ता पर दिया जाए, जो मृदा क्षरण हो रहा है उसे सही करने का प्रयास किया जाए, सिचाई के लिए सुविधाएं दी जाए, किषानो को सस्ते दामों पर बीज और खाद मुहैया कराई जाए। गाँव में जब कृषि की स्थिति ठीक होगी तो आर्थिक खुशहाली भी आएगी और गाँव के लोग रोजगार के लिए बाहर भी नहीं जाएंगे।

सांसद आदर्श ग्राम योजना में विकास के कुछ प्रस्ताव तैयार किये गए जो सुनने में बहुत ही अच्छे लगते है और उसे गाँवों के ऊपर थोप दिया गया। इन विकास योजनाओं को गावों में लागू करने से पहले आवश्यक था की उन गाँव का अध्ययन किया जाता वहां की संस्कृति कैसी है, परम्पराएं क्या है और गाँव की जरूरते क्या है उसके बाद उस आधार पर विकास कार्यक्रम बनाकर लागू किया जाता तो शायद वह ज्यादा कारगर होता।

माननीय सांसद मनोज सिन्हा के गाँव दुल्लहपुर में ग्रामीणों का कहना है की सांसद जी गाँव में केवल दो बार आये है और वो गाँव में अन्दर कभी नही गए। दुल्लहपुर के लिए आवश्यक है की मनोज सिन्हा जी गाँव में अन्दर घूम कर देखते की उनके आदर्श गाँव की स्थिति क्या है। मनोज सिन्हा जो स्वयं ग्रामीण क्षेत्र से सम्बन्ध रखते है वो अपने गोद लिए गाँव की आवश्यकताओं को नहीं समझ पाए है और गोद लिए गाँव के विकास के प्रयासों में बिलकुल ही विफल रहे है।

किसी भी गाँव के विकास के लिए आवश्यक है की वहाँ के लोग जागरुक हो, अपने आस-पास स्वछता, पर्यावरण इत्यादि का ध्यान स्वयं रखे। किसी गाँव का विकास केंद्र या राज्य द्वारा चलाये जा रहे किसी योजना से ज्यादा वहां के लोगों पर ही निर्भर करता है। प्रकृति ने संसाधन दिए है बस उसे उपयोग करने के सही तरीके मालुम करने की आवश्यकता है विकास स्वयं होने लगेगा।